दैनिक

क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय

हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुपी होटल के बगल में, सूरत-394210

मो. 9879141480

क्रांति समय

हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्स्योरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुपी होटल के बगल में, सूरत-394210

मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 244, शनिवार, 29 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्टर्ड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

रेस्टोरेंट के वाशरूम में महिला का वीडियो बनाने के आरोप में कर्मचारी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट के वाशरूम में मलिहा गेस्ट का वीडियो बनाने के आरोप में रेस्टोरेंट के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की शाम महिला अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि जब वाशरूम में गई तो वहां मौजूद एक छेद से कोई उसका वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाए जाने की बात जैसे ही महिला को पता चला वैसे ही उसने पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी दी। महिला ने पुलिस से गुजारिश की कि उसका वीडियो वायरल न होने पाए। डीसीपी मधुर वर्मा ने बताया कि महिला ने घटना की सूचना दी लेकिन वह इसे लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले के आरोपी 20 वर्षीय युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है।

दूसरी शराब फैक्ट्री से एक मजदूर गिरफ्तार

गाजियाबाद, हिटी। डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी में चल रही दूसरी फैक्टरी रवि के अपने फ्लैट में चल रही थी। मौके से फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर अरविंद पुत्र गुलाब सिंह मूल निवासी इटावा पकड़ा गया है। एक अगस्त 2017 पुलिस ने रवि के इसी फ्लैट पर छापा मारकर नकली शराब फैक्टरी का भंडाफोड़ किया था। सवाल यह उठता है कि पुलिस ने उस समय इस फ्लैट को सील क्यों नही किया था? दूसरा अहम सवाल यह है कि गुरुवार को दोबारा इसी फ्लैट में नकली शराब फैक्टरी पकड़ी गई है, आखिर पुलिस की नजर इस फ्लैट पर क्यों नही थी? कहीं ऐसा तो नही कि दोनों शराब फैक्टरियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो। जिसके चलते रवि बेधडक नकली शराब फैक्टरियों का संचालन कर रहा था। नकली शराब फैक्टरियों का संचालन कैसे हो रहा था इसकी जांच कराई जाएगी। अगर पुलिस की संलिप्ता पाई गई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि लोनी क्षेत्र के आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को संतुति भेजी जा रही है।

सर्जिकल स्ट्राइक को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना सैनिकों का सच्चा सम्मान: शाह

एजेंसी,नई दिल्ली। सर्जिकल स्ट्राइक को जवानों के अदम्य साहस का परिचायक बताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना भारतीय सैनिकों के शौर्य को सच्चा सम्मान है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, ''आज से 2 वर्ष पूर्व भारतीय सेना के जांबाजों द्वारा दुश्मनों के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त कर सुरक्षित वापस आना हमारे जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का परिचायक है। उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार द्वारा इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना देश की सुरक्षा के लिये सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे सभी भारतीय सैनिकों के शौर्य को सच्चा सम्मान है। उल्लेखनीय है कि उरी में सेना के ठिकाने पर हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। रक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर 28 से 30 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोधपुर सैन्य अड्डे के बैटल एक्स मैदान में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया जो 2016 में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित की गयी है।

आप का ''दिल्ली की बात, चाय के साथ' कैंपेन लांच

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ''दिल्ली की बात, चाय के साथ' कैंपेन लांच किया है। फिलहाल पार्टी ने इस अंदाज में चुनावी अभियान उत्तर-पूर्वी लोक सभा क्षेत्र में किया है। पार्टी नेता व लोकसभा प्रभारी दिलीप पांडेय का कहना है कि आगे दूसरी लोक सभा क्षेत्रों में भी चाय पर चर्चा होगी। अभी फिलहाल उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी एलान से पहले लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए चाय का सहारा लिया जा रहा है।

ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ दवा की दुकाने बंद, मरीजों को हो रही परेशानी

नई दिल्ली, एजेंसी। दवा व्यापार में ई-फॉर्मेसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त को जारी ड्रॉफ्ट के विरोध समेत अन्य मांगों के समर्थन में दवा व्यापारियों ने पूरे प्रदेश में शुक्रवार को दुकानें बंद रखीं।

दवा व्यापारियों का कहना है कि ई-फॉर्मेसी को बढ़ावा देने से इसका असर सीधे मरीजों पर पड़ेगा। लोग गलत दवाएं मंगा लेंगे। उनकी जांच के लिए सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दवा दुकानें ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बैनर तले पूरे भारत में बंद का असर देखने को मिला।

मरीज और तीमारदार दवा लेने के लिए बाजारों में भटकते रहे। वहीं, सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा लेने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। अधिक भीड़ और अव्यवस्था के चलते सरकारी अस्पताल में तो कई जगह मरीज बिना दवा लिए लौट गए। हालांकि आपात स्थिति में अस्पतालों और नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर को इससे छूट दी गई है। दवा विक्रेता संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन फर्मेसी से दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यही नहीं इसका असर दुकानदारों और उससे जुड़े कर्मचारियों के रोजगार पर भी पड़ेगा।

गाजियाबाद में व्यापारियों ने लगाया जाम-

दिल्ली-एनसीआर में मेडिकल स्टोर के अलावा संयुक्त व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद की। गाजियाबाद के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह व्यापारियों ने जाम लगाया और मेडिकल स्टोर समेत कई दुकाने बंद की। दवा की दुकानें बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

झारखंड में मिलाजुला असर-

झारखंड के कोल्हान में व्यापारियों के भारत बंद का मिलाजुला असर है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में कहीं दुकानें बंद हैं तो कहीं खुली हैं। हालांकि दवा की दुकानें बंद हैं। कदमा में सभी दुकानें खुलीं हैं,जबकि बिष्टूपुर में दुकानें बंद हैं। साकची की सभी दवा दुकानें बंद है जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन ने साकची चौधरी बिल्डिंग के निकट धरना दिया। जुगसलाई बागबेड़ा रोड में बंद दुकाने हैं। पेट्रोल पंप भी बंद है। घाटशिला समेत अन्य शहरों में दवा की दुकानें बंद हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा,चक्रधरपुर समेत अन्य शहरों में दवा की दुकानें बंद हैं। सरायकेल-खरसावां में ऐसी ही स्थिति है।

उत्तराखंड में दवा कारोबारियों की हड़ताल, भटकने को मजबूर मरीज-

ई-फार्मेसी एक्ट के विरोध में राजधानी देहरादून में आज दवा कारोबारी हड़ताल पर हैं। दवा की दुकानें बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के सभी केमिस्ट दून अस्पताल के पास जैन मेडिकल हाल पर एकत्र हुए हैं। यहां से डीएम कार्यालय कूच कर पीएम के नाम एक ज्ञापन देंगे।

यूपी में 1.12 लाख दुकानें बंद, 90 करोड़ का असर-

कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उप्र. के आवाह्न पर शुक्रवार को राजधानी की सभी दवा दुकानें बंद रहीं। लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन लखनऊ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार और कोषाध्यक्ष सुदीप दुबे ने संयुक्त रूप से बताया कि लखनऊ की सबसे प्रमुख बाजार अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट, गोमती नगर, अलीगंज, कैसरबाग, आलमबाग, चौक, मेडिकल कॉलेज समेत अन्य इलाकों में होलसेल व रिटेल की करीब छह हजार दवा दुकानें बंद रहीं। वहीं, प्रदेश में करीब एक लाख 12 हजार दवा

दुकानों पर ताला लटका रहा। दुकानदारों ने अमीनाबाद समेत अलग-अलग जगह पर सड़क पर सभाएं भी की। दुकानें बंद होने से करीब 90 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित रहा। खरीद और बिक्री दोनों पर असर रहा।

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट (एआईओसीडी) के संगठन सचिव और रिटेल डिस्ट्रब्यूटर्स केमिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप नांगिया ने बताया कि केंद्र सरकार ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर एक ड्रॉफ्ट पॉलिसी तैयार की है। उसके विरोध में हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर रहे है। इसमें देशभर के करीब 8 लाख दवा विक्रेता शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर अस्पतालों और नर्सिंग होम में मौजूद मेडिकल स्टोर को इससे छूट दी गई है। एआईओसीडी के अध्यक्ष जेएस शिंदे ने बताया कि ऑनलाइन फार्मेसी पूरी तरह से व्यापार करने का जरिया है। देश में स्वास्थ्य व्यापार का केंद्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना रोक-टोक के ऑनलाइन फार्मेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाना मुश्किल होगा।

आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 300 लोगों को ठगा

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-16 स्थित जेजे कॉलोनी में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नाम पर शातिर ने 300 गरीब लोगों से ठगी कर ली। आरोपी ने योजना का लाभ दिलाने के लिए उनके फॉर्म भरने के बदले में 100-100 रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलने पर बुधवार को लोगों ने पकड़कर आरोपी की धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आयुष्मान भारत योजना को महज तीन दिन हुए हैं। अभी सही से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसी का चालबाज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला महेशचंद कार से सेक्टर-16 जेजे कॉलोनी पहुंचा।

युवक ने लोगों को इस योजना के बारे बताया और रकम दिलाने का लालच देकर 100-100 रुपये में फॉर्म भरने शुरू कर दिए। आरोपी करीब 100 लोगों के फॉर्म भरने के बाद वापस लौट गया। बुधवार को आरोपी फिर से करीब 300 फॉर्म लेकर जेजे कॉलोनी पहुंचा था। इस बीच कॉलोनी में रहने वाला सलीम नामक शख्स वहां पहुंचा। उसने युवक से पूछताछ करनी शुरू कर दी तो आरोपी भागने लगा। इस पर लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई कर दी।

नोएडा : ग्राइंडर की ब्लेड बदल रहा था युवक, तभी किसी ने चालू कर दी मशीन, हुई मौत

नई दिल्ली। नोएडा के एनएसइजेड स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार को एक युवक मशीन की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक (24) वाजिद मूलरूप से छपरा बिहार का रहने वाले थे और सलारपुर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वाजिद उस दौरान मशीन की सफाई कर रहा था, तभी किसी ने मशीन को चालू कर दी और मशीन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सलारपुर कॉलोनी में किराये के मकान में रहने वाले वाजिद (25) की दस अगस्त को एनएसईजेड स्थित प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्टरी में मशीन ऑपरेटर की नौकरी लगी थी। बुधवार सुबह 9 बजे फैक्ट्री में पहुंचकर वाजिद ने मशीन को बंद करके उसकी साफ-सफाई शुरू की। वाजिद मशीन का ब्लेड बदल रहा था, तभी किसी कर्मचारी ने मशीन का स्विच ऑन कर दिया। इससे मशीन तेज गति से चल गई और वाजिद बुरी तरह कुचले गया। मशीन के पास खड़े अन्य कर्मचारी भी खून से सन गए। पुलिस का कहना है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस मशीन स्विच ऑन करने के आरोपित की तलाश कर रही है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने कंपनी के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने फैक्ट्री के दो लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। क्षेत्राधिकारी तृतीय श्वेताभ पांडेय का कहना है कि कर्मचारी मशीन की सफाई कर रहा था। इसी दौरान किसी कर्मचारी ने मशीन को चालू कर दिया और ऑपरेटर की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मशीन को चालू करने वाले आरोपित कर्मचारी की तलाश की जा रही है। साथ ही परिजनों के आरोपों की भी जांच की जा रही है।

711 रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही मुफ्त वाईफाई है और उनका लक्ष्य अगले चार महीनों में 6,000 स्टेशन के आकड़ों तक पहुंचने का है।

पीयूष गोयल ने कहा- चार महीनों में सभी रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई संभव

एजेंसी,नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि अगर गूगल जैसी निजी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी में सफलता मिलती है तो अगले चार महीनों में रेलवे नेटवर्क के सभी 6,000 स्टशनों पर मुफ्त वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

गूगल कल्चरल इंस्टीट्यूट के सहयोग वाली 'द रेलवेज- लाइफलाइन ऑफ द नेशन' परियोजना के शुभारंभ पर उन्होंने कहा 711 रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही मुफ्त वाईफाई है और उनका लक्ष्य अगले चार महीनों में 6,000 स्टेशन के आकड़ों तक पहुंचने का है।

उन्होंने कहा, 'गूगल ने रेलवे के साथ मिलकर 400 से ऊपर स्टेशनों पर मुफ्त वाईफई सुविधा उपलब्ध कराई है। यह दिखाता है कि साझेदारी में कितनी ताकत है और लोगों की सेवा के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।'

गोयल ने कहा, 'हमें इसे सभी 6000 स्टेशनों तक पहुंचाना है ताकि स्टेशन के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोग खासकर गरीब या समाज के वंचित वर्गों के लोग देश के विकास का स्वाद ले सकें।'

इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने साझेदारी की जरूरत पर प्रकाश डाला और अन्य स्टेशनों पर भी मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए गूगल से रेलवे के साथ साझेदारी करने की अपील की।

दिल्ली में 11 साल की मासूम से सहेली के पिता ने घर में किया रेप

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व दिल्ली के जैतपुर इलाके में बुधवार को 11 साल की बच्ची से सहेली के पिता ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पोक्सो एवं दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है।

सहेली के घर गई थी-

जानकारी के अनुसार, पीड़िता परिवार सहित जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर में रहती है। घर के पास ही बच्ची की सहेली भी रहती है, जिसके साथ वह स्कूल जाती थी। बताया गया कि बुधवार को बच्ची अपनी सहेली के घर गई थी। तब सहेली घर पर नहीं थी, लेकिन उसके पिता महेंद्र मौजूद थे। बच्ची वापस अपने घर जाने लगी तो आरोपी ने उसे रोक लिया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

गुरुवार को भोपाल में कला सानिया स्थित पुलिस एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेश आरके शुक्ला भी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों को विवाहित लोगों को अवैध संबंध रखने की खुली छूट दी : स्वाति

व्यभिचार पर कोर्ट के फैसले से स्वाति मालीवाल असहमत

नई दिल्ली, एजेंसी दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने व्यभिचार को गैर आपराधिक घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले पर असहमति और दुःख व्यक्त करते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि व्यभिचार को गैर आपराधिक घोषित करके उच्चतम न्यायालय ने इस देश के लोगों को शादी से बाहर अवैध संबंध रखने की खुली छूट दे दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय को अवैध संबंधों को बिना लिंग भेद के महिला और पुरुष दोनों के लिए आपराधिक करना चाहिए था। इसकी जगह उन्होंने व्यभिचार को ही गैर आपराधिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष महिलाओं की ऐसी हजारों शिकायतें आती हैं जिनमें उनके पतियों के शादी से बाहर अवैध संबंध हैं और उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है। यह महिलाएं अपने पति के सहारे के बिना खुद का और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अकेली छोड़ दी जाती हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के ऊपर अधिकार के भाव की वजह से पुरु ष खराब वैवाहिक संबंधों के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस परिदृश्य में व्यभिचार को गैर आपराधिक घोषित करना महिलाओं के दर्द को और ज्यादा बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने समाज के एक बड़े तबके की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस फैसले के सन्दर्भ में एक सर्वे शुरू किया है जिसमें अवैध संबंधों की वजह से पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की परेशानियों और उन पर पड़ने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। आयोग ने इस मामले में लोगों से राय मांगी है। उन्होंने कहा कि अपने पतियों के व्यभिचार की वजह से जो पीड़ित महिलाएं हैं वह आयोग को पर मेल करके इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं।

गुण ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। गुण सभी स्थानों पर अपना आदर करा लेता है -कालिदास

''लोक प्रहरी'

न्यायालय द्वारा जन प्रतिनिधियों की सजा पर स्थगनादेश मिलने पर सदस्यता की पुनर्बहाली का आदेश निस्संदेह इस श्रेणी के नेताओं के लिए बड़ी राहत है। 2013 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होते ही जन प्रतिनिधियों की संसद और राज्य विधायिकाओं की सदस्यता खत्म मानी जाएगी। भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति को मुक्त करने की दिशा में वह अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण फैसला था। यह कहना गलत होगा कि न्यायालय ने अपने फैसले में कोई बदलाव किया है। किंतु न्याय का तकाजा है कि अगर अपीलीय न्यायालय किसी सजा पर स्थगनादेश लगाता है तो उसके सारे परिणाम बदल जाने चाहिए। स्थगनादेश का मतलब ही हुआ कि न्यायालय द्वारा दी गई सजा अब जारी नहीं है। जब सजा ही जारी नहीं है तो फिर किसी जन प्रतिनिधि की सदस्यता कैसे जा सकती है? न्यायालय ने साफकिया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में सिर्फ सजा को स्थगित करने का प्रावधान ही नहीं है बल्कि दोषसिद्धि पर स्थगनादेश का भी अधिकार अपीलीय न्यायायल को दिया गया है। ''लोक प्रहरी' नामक संस्था ने उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया था। उक्त विधायक को न्यायालय ने दोषी ठहराया था। विधायक ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील की, जिसने दोषसिद्धि पर स्थगनादेश दे दिया और इस तरह विधायक की विधानसभा का सदस्यता बहाल हो गई। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब दोषसिद्ध होने पर जिसे भी अपीलीय न्यायालय में स्थगनादेश मिल गया वह उस तिथि से ही संसद या राज्य विधायिकाओं के संबंधित सदन का सदस्य माना जाएगा जिस तिथि से उसे सजा मिली थी। ऐसा ही होना चाहिए। सजा मिल गई तो उसकी सदस्यता गई, लेकिन यदि सजा स्थगित हो गई तो उसकी सदस्यता केवल स्थगनादेश से बहाल करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि जिस बीच में वे सदस्य नहीं रहे उसका आधार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करके इस तरह के प्रश्न को उभरने से पहले ही खत्म कर दिया है। हालांकि अभी इसमें कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मिलना शेष है। मसलन, यदि स्थगनादेश के बाद फिर से सजा मिल गई तो क्या होगा? सजा और स्थगनादेश और पुनः सजा के बीच सदस्यता की स्थिति क्या मानी जाएगी? बहरहाल, इस प्रश्न का उत्तर भविष्य में जरूर मिलेगा।

लापरवाही का नतीजा

अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा क्या होता है, यह उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार इलाके में जमींदोज हुए इमारत में रहने वालों से पूछिए। बुधवार को साल भर से शीशम के सूखे पेड़ के सहारे टिकी पांच मंजिला इमारत भरभराकर धूल चाटने लगी। इस घटना में कुल सात लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग जख्मी हो गए। स्थानीय निवासियों और इस हादसे में बच गए लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कापरेरेशन (एमसीडी) को साल भर से ज्यादा समय से इस इमारत की कमजोर हालत के बारे में शिकायत की गई थी, मगर अधिकारी चुप्पी साधे रहे। साल भर से ज्यादा समय से इमारत एक फुट से अधिक एक ओर झुक गई थी। लगातार शिकायतों के बाद एमसीडी की टीम ने 15 दिन पहले इमारत का निरीक्षण भी किया था, मगर वही ढाक के तीन पात। सब कुछ देख-सुनकर भी उन्होंने दूरी बना ली। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) का मानना है कि दिल्ली में ही करीब 80 फीसद भवनों का निर्माण नियमों की अनदेखी करके किया गया है। साथ ही निर्माण संबंधी विनियमनों की निगरानी के अभाव में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इमारतों का खासा बड़ा हिस्सा सुरक्षित नहीं है। इस सच्चाई को जानकर भी तंत्र अनजान बना हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि नये भवनों के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड-2005, दिल्ली के मस्टर प्लान-2021, वल्नरेबिलिटी एटलस-2006, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों या आवास निर्माण, विकास एवं नियामक प्राधिकरणों द्वारा तय तरीकों के तहत किए जाते हों। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। तमाम शिकायतों के बावजूद अगर देश की राजधानी के एक इलाके में ऐसी घनघोर लापरवाही हो रही है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हो रहा होगा, अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या सरकार और सिस्टम अब भी नहीं चेतेगी? अनुमान है कि दिल्ली में कमजोर भवनों की संख्या करीब 25 लाख है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें रह रहे लोग अपनी जिंदगी को किस तरह दांव पर लगाए हुए हैं। इस नाते सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, इलाकों का सव्रे कर कमजोर इमारतों की सूची बनाकर उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। क्योंकि लापरवाही और लीपापोती को परे रखकर ही कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

सत्संग

आध्यात्मिकता

पूरे जीवन की कोशिश यही रही है कि रहस्यवाद को, आध्यात्मिकता को सरल व तार्किक तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, ग्रहण कर सकें। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, जो आसान चीजों को भी रहस्यमय या दैवीय बनाने में लगे हैं। अगर कहीं घंटी बजती है या कोई फूल गिरता है या फिर अगर बिजली चली जाती है, तो लोग इसमें दैवीय आयाम ढूंढने लगते हैं। दैवीय आयाम को इंसानों की पहुंच में लाने के बजाय वे लोग जीवन के सहज व सरल पक्षों (भागों) को दूसरे आयामों में ले जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि आप ध्यान का इस्तेमाल अपनी समस्याओं के समाधान के तौर पर करने की कोशिश मत कीजिए। सवाल है कि क्यों? हमें अपनी समस्याओं के समाधान में ध्यान का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? दरअसल, यह तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि मामूली से जुकाम को ठीक करने के लिए आप कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करें। जीवन को संभालने का यह मूर्खतापूर्ण तरीका है। मामूली से जुकाम को संभालने के लिए रुमाल काफी है। जुकाम में आपको कुछ दिनों तक नाक बहानी होगी, अदरक या काली मिर्च की चाय पीनी होगी और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो उस दौरान आप मानव अस्तित्व की सबसे मूलभूत समस्या से निबटने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल मामूली चीजों के लिए मत कीजिए। अगर आप मानव अस्तित्व की सबसे बुनियादी समस्या से निबटने की कोशिश करते हैं तो बाकी सभी समस्याएं तुच्छ और अर्थहीन नजर आती हैं। अगर आप इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं। यह बेहद अफसोस की बात है कि जब आप ध्यान करते हैं, केवल तभी आपके मन में कुछ स्पष्टता रहती है, बाकी समय आपके मन में भारी हलचल या कोलाहल रहता है। इसकी वजह है आपके भीतर बुनियादी तौर पर एक भ्रम है। हम ईशा क्रिया द्वारा इसको सरल तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं। क्रिया के दौरान कहा जाता है-''न ही मैं शरीर हूं और न ही मन हूं।' अगर आपने यह चीज अनुभव के स्तर पर समझ ली तो आपकी बाकी समस्याएं एक झटके में गायब हो जाएंगी। अगर आप अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति को जानते तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए महज एक खेल होतीं, एक नाटक होता।

दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण

सरकार के पास ये भी आंकड़े होने चाहिए कि आदिवासियों व दलितों का प्रतिनिधित्व का अभाव है। 2006 के इस फैसले को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों को लागू करने में कानून के व्याख्याकारों द्वारा अड़चनें पैदा की जा रही थी। तब सरकार के समाने एक विकल्प था कि वह अब तक कानूनी व्याख्या की जितनी अड़चनें खड़ी हुई है, उन्हें दूर करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाए लेकिन राजनीतिक कारणों से सरकार इस रास्ते के बजाय सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सरकार के साथ सामाजिक न्याय को लागू करने की चुनौती को पूरा करने में लगी संस्थाएं और व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की एक प्रक्रिया में लगे कि दलितों व आदिवासियों के आरक्षण और पदोन्नति के लिए उनके पिछड़ेपन के आंकड़ों की जरूरत नहीं है।

सतीश पेडणोकर

सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण और जिन्हें नौकरियां मिल गई है उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुसार सरकारें तय करती है, लेकिन जिन्हें आरक्षण की व्यवस्था से एतराज होता है वे संसद व विधानसभाओं द्वारा आरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों को संविधान की मूल भावना पर चोट पड़ने की शिकायत के साथ अदालत चले जाते हैं। न्यायालय संसद व विधानसभाओं द्वारा किए गए प्रावधानों की व्याख्या अपने स्तर पर करता है। इस रस्साकशी का एक लंबा इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति की प्रक्रिया में भी आरक्षण के प्रावधानों को लेकर जो अपना मत जाहिर किया है, वह इस इतिहास की नवीनतम कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने 19 अक्टूबर 2006 को एक फैसला सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट के सामने यह शिकायत की गई थी कि संसद ने अनुच्छेद 335 में की गई व्यवस्था के अनुसार आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 (4) में संविधान संशोधन किया है और यह समानता के सिद्धांत के विरु द्ध है। इस शिकायत को एस नागराज बनाम सरकार के रूप में जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य व केंद्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो प्रावधान कर रही है, उसके लिए उसके पास दलितों व आदिवासियों के पिछड़ेपन के बारे में पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए। सरकार के पास ये भी आंकड़े होने चाहिए कि आदिवासियों व दलितों का प्रतिनिधित्व का अभाव है। 2006 के इस फैसले को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों को लागू करने में कानून के व्याख्याकारों द्वारा अड़चनें पैदा की जा रही थी। तब सरकार के समाने एक विकल्प था कि वह अब तक कानूनी व्याख्या की जितनी अड़चनें खड़ी हुई है, उन्हें दूर करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाए लेकिन राजनीतिक कारणों से सरकार इस रास्ते के बजाय सुप्रीम कोर्ट के सामने गई।

सरकार के साथ सामाजिक न्याय को लागू करने की चुनौती को पूरा करने में लगी संस्थाएं और व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की एक प्रक्रिया में लगे कि दलितों व आदिवासियों के आरक्षण और पदोन्नति के लिए उनके पिछड़ेपन के आंकड़ों की जरूरत नहीं है। क्योंकि दलितों और आदिवासियों की सामाजिक स्थिति पिछड़े वगरे से भिन्न रही है। पिछड़े वगरे के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है।

दलित और आदिवासी समाज से बहिष्कृत की स्थिति में सदियों से रह रहे हैं। 30 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितम्बर को यह कहा कि पिछड़ेपन का आंकड़ा जुटाने की जरूरत सरकार को नहीं है। इस फैसले पर गौर करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट संसद और विधानसभाओं द्वारा नये प्रावधान करने के अधिकार को तो स्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें लागू करने के लिए मानदंड तैयार करने का मसला संविधान की व्याख्याओं पर आकर टिक जाता है और व्याख्याएं करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। इस फैसले के आधार पर हम मौटे तौर ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। परंतु उसने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करते वक्त पिछड़े वर्ग की तरह दलितों और आदिवासियों में क्रीमीलेयर के सिद्धांत और प्रशासनिक दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन की जरूरत को उसमें शामिल कर लिया है। जब राजनीतिक स्तर पर सामाजिक तौर पर वंचित वगरे की ताकत में इजाफा होता है तो आरक्षण और उससे जुड़े दूसरे प्रावधान सामने आते है या फिर राजनीतिक स्तर पर वंचितों के बीच अपने विस्तार की जरूरत करने वाली राजनीतिक शक्तियां आरक्षण जैसे मसले को छूने की कोशिश करती है। न्यायपालिका और संसद के बीच आरक्षण को लेकर जो रस्साकशी चलती हैं, वह राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार एक फैसले के रूप में सामने आती है। हाल के वर्षो में दलितों और आदिवासियों के हितों के लिए किए गए प्रावधानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी है। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 मार्च को किए गए संशोधन और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उक्त कानून को पुरानी स्थिति में लाने के लिए संसद में विधेयक पारित करने की एक प्रक्रिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार न्यायालयों द्वारा किए जा रहे फैसलों के राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंतित रही है। लिहाजा उसे दलित और आदिवासी हितों के अनुकूल दिखने की कवायद से गुजरना पड़ता है, जबकि सत्ताधारी पार्टी का सामाजिक आधार न्यायापालिका द्वारा किए गए संशोधनों की पक्षधर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितम्बर के फैसले को दलितों और आदिवासियों के बीच पनप रहे असंतोष और असंतोष को जाहिर करने के लिए आंदोलनरत होने की स्थिति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अपने संघर्षो के बूते अपने लिये दलित और आदिवासी संबोधनों को जिस तरह से इन वगरे ने सुरक्षित रखा है, उसी संघर्ष की यह कड़ी है कि एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार को पदोन्नति में कोटे को न्यायोचित ठहराने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह एक प्रमाणित तय है कि सरकार के ऊंचे पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों की संख्या न के बराबर होती है। 21 मार्च 2018 को राज्य सभा में भाजपा के डॉ. सत्यनारायण जटिया के एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि पीएसबी में अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय महाप्रबंधक के स्तर पर अजा और अजजा के लिए कोई आरक्षण नहीं है। 28 मार्च को लोक सभा में सरकार के एक जवाब के मुताबिक 77 मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों में 1 जनवरी 2016 तक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 17.29 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 8.47 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 21.5 प्रतिशत होने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जो फैसला सुनाया था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। सो, आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था से ही आरक्षण का संवैधानिक सिद्धांत मुक्कमल होता है।

चलते चलते

शर्मनाक स्थिति

राज्य में शासन व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का अपराधियों से हाथ जोड़कर पितृपक्ष के दौरान वारदातें रोकने के लिए अर्ज करते हुए दिखे। बयान के बाद के अगर-मगर को एक तरफरख दें तो राज्य में हाल के समय में घटित वारदातें उप मुख्यमंत्री की बेबसी बताने को काफी हैं। बीते रविवार को मुजफ्फरपुर में शहर के पूर्व महापौर समीर कुमार की हत्या कर दी गई।

राज्य व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी, जब उसका दूसरे नंबर का प्रमुख एक विशेष अवधि के लिए अपराधियों से अपराध रोकने के लिए मिन्नतें करे। इसका स्पष्ट संदेश तो यही जाता है कि राज्य में शासन व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का अपराधियों से हाथ जोड़कर पितृपक्ष के दौरान वारदातें रोकने के लिए अर्ज करते हुए दिखे। बयान के बाद के अगर-मगर को एक तरफरख दें तो राज्य में हाल के समय में घटित वारदातें उप मुख्यमंत्री की बेबसी बताने को काफी हैं। बीते रविवार को मुजफ्फरपुर में शहर के पूर्व महापौर समीर कुमार की हत्या कर दी गई। हत्या में एके-47 का इस्तेमाल अपराधियों के मनोबल और सरकार की साख को परिभाषित करने के लिए काफी है। घटना यह भी बताती है कि अपराध की संस्कृति राज्य में बहुत कमजोर नहीं पड़ी है। एक समय राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के पर्यायवाची से बन गए बिहार में 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद फिजा में बदलाव के दावे किए गए। राज्य के तत्कालीन पुलिस प्रमुख अभयानंद के स्पीडी ट्रायल प्रयोग को अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में कुछ हद तक सफल भी माना गया। मगर हाल में एक महिला को बिहिया (भोजपुर) में जिस प्रकार भीड़ ने सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही, उसने देश भर में बिहार के जंगलराज वाले माहौल की याद ताजा कर दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह काण्ड में समाज कल्याण मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। इस काण्ड ने तंत्र के सड़ांध को सतह पर ला दिया। विशेषकर महिला सुरक्षा के संदर्भ में आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। 2017 के दौरान जहां 15,784 मामले सामने आए थे, वहीं इस साल सिर्फ जून तक 7683 मामले सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री के बयान का सीधा असर पुलिस को मनोबल पर पड़ेगा। वह जिस गठबंधन सरकार के हिस्सा हैं, अगर वो कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में अक्षम है तो विपक्षी दलों की बात सही होती दिखती है कि सरकार की हनक नहीं रह गई है।

फोटोग्राफी...

ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर में दिखाया समुद्र पर पड़ती इमारतों की छाया का दृश्य

यह फोटो ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर ग्लेनेल्ग का है, जहां सुबह के वक्त इमारतों के कारण समुद्र किनारे इमारतों की छाया दिखने लगती है। यह फोटो रोमानिया के फोटोग्राफर पॉल व्लाड एप्यू रे ने क्लिक किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले जब मैं वहां पहुंचा, तो सुबह के वक्त सैर करने तट पर पहुंच गया था। वहां मैंने इमारतों की छाया का दृश्य देखा। उसे कैमरे में कैप्चर करने के लिए अगली सुबह फिर वहीं पहुंचा और एरियल शॉट क्लिक किया। वह तो अच्छा था कि मुझे दोनों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ मिला और सुबह के वक्त अच्छी धूप खिलने के कारण में यह फोटो क्लिक कर पाया। nationalgeographic.com

जादुई आवाज

ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है तो जसदेव सिंह आवाज के जादूगर थे। लेकिन यह आवाज अब खामोश हो गई है। जादुई आवाज के साथ रेडियो से रोमांस करने वाले जसदेव सिंह का 25 सितम्बर को लंबी बीमारी के बाद 87 साल की उम्र में निधन हो गया। जसदेव सिंह ने रेडियो से लेकर टेलीविजन तक पर कमेंट्री की। लेकिन रेडियो के जमाने में वह देशभर में सिर्फ आवाज से पहचाने जाते थे और ज्यादातर लोगों को यह पता तक नहीं था कि वह दिखने में कैसे लगते हैं। वह पिछले काफी समय सुर्खियों से दूर थे। करीब दो-तीन पहले वह राजधानी के शिवाजी स्टेडियम में एक टूर्नामेंट में आए थे। उस समय उन्हें कुर्सी पर बैठने तक में मुश्किल हो रही थी। जसदेव सिंह की आवाज की दीवानगी कैसी थी, इसको आप इस किस्से से समझ सकते हैं। मलयेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में 1975 के हॉकी विश्व कप में भारत विश्व विजेता बनकर लौटा। हॉकी टीम का देशभर में स्वागत किया गया। जसदेव सिंह भी हॉकी टीम के साथ इन समारोहों में गए थे। ऐसा ही एक समारोह लखनऊ के स्टेटिडयम में आयोजित किया गया। इस समारोह का संचालन भारत के पूर्व हॉकी कप्तान केडी सिंह बाबू कर रहे थे। बाबू ने भारतीय टीम को सम्मानित करने के बाद कहा कि अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे, जो आपके दिलों में राज करती है पर आप उसे पहचानते नहीं हैं। केडी सिंह बाबू ने जसदेव सिंह का परिचय इस प्रकार दिया कि गेंद समीउल्ला से वसीउल्ला को और गेंद समीउल्ला पर लौटी और उन्होंने तेज आवाज में कहा कि गोल। कहने का मतलब यह है कि उनके अंदाज में बोलने से ही लोग समझ जाते थे कि किस की बात हो रही है। पहली बार विश्व कप जीतकर लौटी भारतीय टीम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गई। टीम के साथ कमेंटेटर जसदेव सिंह भी थे। इस मौके पर इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मैंने संसद की छुट्टी करवाकर सभी के साथ फाइनल की आपकी कमेंट्री सुनी और आपने तो दिलों की धड़कनों को ही बढ़ा दिया। आप इतनी तेजी से कैसे बोल पाते हैं? साथी कमेंटेटर रहे डॉ. नरोत्तम पुरी कहते हैं कि जसदेव सिंह की आवाज बहुत साफ थी और वह इसे बहुत तेजी से बोलने में सक्षम थे। वह कुछ शब्दों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया करते थे। जसदेव सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह 1948 में अपनी मां के साथ बैठकर महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में मैलविल डिमेलो से सुन रहे थे और इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने कमेंटेटर बनने का फैसला कर लिया। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह 1955 में जयपुर रेडियो से जुड़ गए। बाद में वह दिल्ली रेडियो से जुड़ने में कामयाब हो गए। जसदेव सिंह मुख्यतः गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह, हस्तियों की अंतिम यात्राओं के साथ हॉकी की कमेंट्री किया करते थे। बाद में वह क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों की कमेंट्री से भी जुड़े। पर यह सच है कि हॉकी का जिस तरह उन्हें अच्छा ज्ञान था, वैसा क्रिकेट आदि खेलों का नहीं था। अनकी क्रिकेट कमेंट्री का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जसदेव सिंह ने हिंदी कमेंट्री की न सिर्फ शुरुआत की बल्कि इसे लोकप्रिय भी बनाया। जसदेव सिंह हॉकी मैचों का ऐसा सचीव चितण्रपेश करते थे कि कई बार लगता था कि हम मैदान में ही बैठे हैं। जसदेव सिंह कमेंट्री करने से काफी पहले स्थल पर जाकर कमेंट्री की तैयारी किया करते थे क्योंकि उस समय आंकड़े एक क्लिक पर मौजूद नहीं होते थे। इन सब बातों के बावजूद हिंदी कमेंट्री को इतना लोकप्रिय बनाया, जिसके लिए सारा देश उनका ऋणी रहेगा। यह आवाज जादूगर अब ओझल हो गया है और सिर्फ यादें छोड़ गया है।

चपरासी को ट्रेनिंग देकर ATM से चोरी कराने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, सीबीआई करेगी मामले की जांच

शामली। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से 18.36 लाख रुपये चोरी कराने के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर रोबिन बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 14.36 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। बताया गया कि आरोपी बैंक मैनेजर ने चपरासी को ट्रेनिंग देकर एटीएम से यह चोरी करवाई थी।

वहीं, आरोपी बैंक प्रबंधक ने बनती खेड़ा शाखा से किसानों की फिक्स डिपॉजिट के आधार पर करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन पास कराकर अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवा लिया। इसको लेकर बैंक की तरफ से अलग से जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए बैंक की जोनल शाखा से भी टीम पहुंच गई है, मामला गंभीर होने के कारण सीबीआई को जांच भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि शामली शहर के इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से मार्च माह में 18.37 लाख रुपये चोरी करने की वारदात बंती खेड़ा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर ने अपने चपरासी से अंजाम दिलाई थी। कैश चुराने के बदले चपरासी को 50 हजार रुपये दिए थे। पुलिस ने आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया था।

यह वारदात गत चार मार्च 2018 को हुई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में दो कैश केसेट खराब होने पर बैंक अधिकारियों ने मेरठ स्थित एनसीआर कंपनी को शिकायत दर्ज कराई थी। तीन मार्च को बैंक कर्मी राजीव कुमार व धर्मेंद्र गिरी ने एटीएम में 28 लाख रुपये डाले थे। एटीएम की सुरक्षा बैंक का जनरेटर आपरेटर यशपाल सिंह करता था। इसके बाद चार मार्च को एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा तथा एटीएम मशीन को खोलने लगा, जिस पर यशपाल सिंह ने पूछताछ तो उसने बताया कि वह एनसीआर कंपनी से आया है। इसी बीच बंतीखेड़ा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा प्रबंधक रोबिन बंसल भी वहां पहुंच गए और यशपाल से बात करने लगे थे। इसके बाद आरोपी युवक एटीएम से 18,37,300 रुपये निकालकर ले गया था। घटना की बाबत शाखा प्रबंधक नितेश कुमार ने छह मार्च को शामली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शामली कोतवाली में प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया था कि शामली में विजय चौक के पास से चेतन पुत्र सहेंद्र निवासी बंतीखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह बंतीखेड़ा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में चपरासी है। शामली में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से वह कैश निकालकर ले गया था और बंतीखेड़ा स्थित बैंक शाखा के प्रबंधक रोबिन बंसल को दे दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात को शाखा प्रबंधक रोबिन बंसल ने चपरासी से अंजाम दिलाया। आरोपी रोबिन शामली के मोहल्ला गुजरातियान का रहने वाला है।बंती खेड़ा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक रोबिन बंसल ने चपरासी चेतन को एटीएम से कैश चोरी करने के लिए 50 हजार रुपये दिए थे। गिरफ्तार आरोपी चेतन ने पुलिस को बताया कि वह बैंक शाखा से अपनी शादी के लिए एक लाख रुपये ऋण लेना चाहता था, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उससे कहा कि यदि तुम मेरा कहना मानो, तो मैं तुम्हें बगैर ऋण के ही 50 हजार रुपये दे दूंगा। इसके बाद रोबिन बंसल ने चेतन को एटीएम खोलने की ट्रेनिंग भी दी थी और एटीएम का गोपनीय कोड भी बताया था। गिरफ्तार आरोपी चेतन ने पुलिस को बताया कि एटीएम से कैश निकालने के बाद वह करीब चार घंटे तक घूमता रहा। शामली से निकलने के बाद वह पूर्वी यमुना नहर पटरी के रास्ते मुंडेट गांव पहुंचा और फिर वहां से बंतीखेड़ा स्थित बैंक शाखा में पहुंचकर प्रबंधक रोबिन बंसल को रुपयों से भरा बैग थमा दिया था। इसके बाद रोबिन ने चेतन को 50 हजार रुपये दे दिए थे।पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि रोबिन बंसल पूर्व में इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा शामली में कार्यरत था। इसके चलते उसे एटीएम का गोपनीय कोड मालूम था। बैंक में दूसरे शाखा प्रबंधक की तैनाती होने के बावजूद गोपनीय कोड बदला नहीं गया था, जिसका फायदा रोबिन बंसल ने एटीएम से कैश चोरी कराने में उठा लिया। आरोपी रोबिन बंसल ने एटीएम से कैश चोरी कराने की वारदात में खुद को बचाने के लिए चतुराई भी खूब दिखाई थी। चार मार्च को जब एटीएम से कैश निकाला गया था, तो रोबिन बंसल भी मौके पर पहुंच गया था। एटीएम की सुरक्षा करने वाले जनरेटर ऑपरेटर यशपाल सिंह ने जब रोबिन से कहा कि एटीएम ठीक करने मेरठ से युवक आया है। इस पर दिखावे के लिए रोबिन ने आरोपी से भी पूछा था कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब आरोपी चेतन ने कह दिया था कि एनसीआर कंपनी मेरठ से आया हूं। खास बात यह थी कि एटीएम खोलने वाले ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, देश फतवों से नहीं संविधान से चलेगा

गोरखपुर। मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश किसी फतवे से संचालित नहीं होगा जिसे फतवे के आधार पर संचालित करना चाहते हैं। इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महापुरुषों ने एक संविधान दिया है, उस संविधान से देश को संचालित करने की आवश्यकता है। हम अपनी सुरक्षा चाहते तो भारत की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। अगर हम स्वयं की समृद्धि चाहते हैं तो भारत की समृद्धि की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत की समस्त समस्याओं का समाधान भारत के संविधान से होगा।

संविधान के दायरे में रह कर जन भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं, देश का उत्थान भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह में महंत दिग्विजयनाथ की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे।

यूपी में नौ ‍ब्ठ्ठस का तबादला, हिमांशु बने कुमार प्रमुख सचिव खनन

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार को स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अतिरिक्त रूप से दिया गया है।नेपाल सिंह रवि सदस्य राजस्व परिषद महानिदेशक प्रशिक्षण, डॉ. अनीता भटनागर जैन महानिदेशक प्रशिक्षण अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, रजनीश गुप्ता सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद,हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि स्टाम्प एवं पंजीयन के साथ प्रशासन तथा स्टाम्प एवं पंजीयन प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म निवेदिता शुक्ला वर्मा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नवीन कुमार जीएस विशेष सचिव चिकित्सा, विशेष सचिव कृषि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं प्रबंध निदेशक उप्र मेडिकल वी. हेकाली झिमोमी सचिव चिकित्सा, वर्तमान पद के साथ प्रबंध निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उप्र मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन अरविन्द कुमार सिंह निदेशक नेडा एवं विशेष सचिव विशेष सचिव पशुधन गैर परंपरागत ऊर्जा परंपरागत स्रोत अमृता सोनी विशेष सचिव ऊर्जा वर्तमान पद के साथ निदेशक नेडा का अतिरिक्त प्रभार।

मेडिकल और आर्ट्स के लिए गणित का सरल पेपर, जानिए परीक्षा पैटर्न में हुए क्या-क्या बदलाव

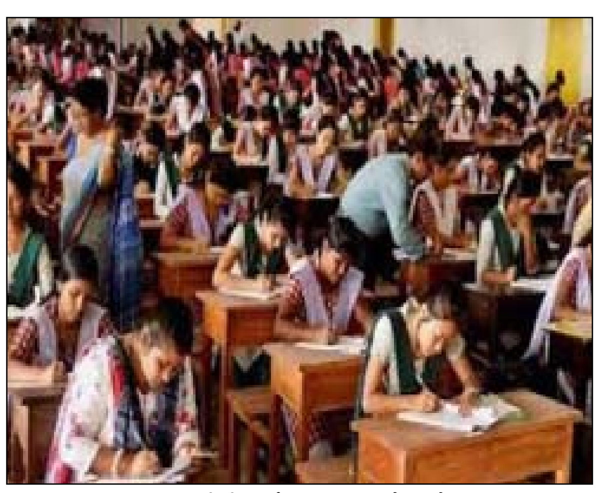

लखनऊ । सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों के पास गणित के दो प्रश्नपत्र होंगे। छात्र इनमें से एक प्रश्नपत्र का चयन कर सकेंगे। इसमें एक प्रश्नपत्र सरल तो दूसरा कठिन होगा। इंजीनियरिंग समेत अन्य गणित से जुड़े क्षेत्रों में करियर बनाने वालों को कठिन प्रश्नपत्र देना होगा जबकि अन्य छात्रों को सरल प्रश्नपत्र चुनकर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा।

पिछले वर्ष सीबीएसई ने सिलेबस सहित परीक्षा पैटर्न में बदलाव के लिए सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर बोर्ड ने यह बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर जावेद आलम खान ने कहा कि जो छात्र मेडिकल या आर्ट्स से जुड़े क्षेत्रों में भविष्य की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको भी बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर देना होता है। इन छात्रों को सहूलियत देने के लिए बोर्ड ने बदलाव किया है। अब इन छात्रों के पास गणित का सरल पेपर उपलब्ध होगा, जिससे इनकी मेरिट भी अच्छी रहेगी। जो छात्र आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और ज्वांइट एंट्रेंस टेस्ट (जेईई) की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड उनके लिए गणित का कठिन पेपर बनाएगा। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर के मुताबिक परीक्षा फार्म भरने के दौरान छात्रों के पास गणित के पेपर का विकल्प उपलब्ध होगा।

इस दौरान गणित के छात्र कठिन प्रश्नपत्र का चुनाव करेंगे जबकि आर्ट्स व मेडिकल में जाने वाले छात्र सरल गणित का विकल्प भरकर फार्म सबमिट करेंगे। जावेद आलम खान ने बताया कि यदि ये छात्र भी कठिन पेपर देना चाहेंगे तो सुविधा भी उपलब्ध होगी। मेडिकल या आर्ट्स पढ़ने वालों के लिए गणित एक चुनौती होता है।

चूंकि उनको भविष्य में इस विषय को छोड़ना होता है इसलिए वे इसमें औसत अंक लाने का ही प्रयास करते हैं। जब गणित का पेपर आसान होगा तो मेडिकल व आर्ट्स के छात्रों को बोर्ड में बेहतर परिणाम मिलेंगे। सीबीएसई में इस बार गणित के दो पेपर होंगे। मेडिकल या आर्ट्स में करियर बनाने वालों के पास गणित का सरल पेपर देने का विकल्प होगा। इंजीनियरिंग में जाने वालों को गणित का कठिन पेपर देना होगा। -जावेद आलम खान, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर

जबरदस्ती जंगल में ले जाकर 12 साल की मासूम से रेप, फिर दी जान से मारने की धमकी

उत्तरप्रदेश के संभल से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां धनारी थाना क्षेत्र के एक गांव बारह साल की किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित किशोरी ने हरियाणा में रह रही मां को घटना के बारे में बताया तो मां के गांव आने के बाद तीसरे दिन मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला का पूरा परिवार हरियाणा में रहकर मजदूरी करता है। अचानक पति की तबीयत खराब होने पर महिला अपने परिवार के साथ गांव में आ गई थी। पति के इलाज को पैसा नहीं था तो किसी तरह अपने घर का गुजारा करने के लिए एक भैंस खरीद ली। लेकिन पति का इलाज नहीं हो पा रहा था। मजबूरी में महिला अपने बीमार पति व 12 साल की बेटी को गांव में छोड़कर हरियाणा में मजदूरी करने के लिए चली गई। मां के जाने के बाद किशोरी अपने पिता की देखभाल करने के काम में लगी थी। मंगलवार की शाम को किशोरी घास लेने के लिए जंगल में गई थी। उसी जगह गांव का एक युवक घास काटने के लिए आ गया। किशोरी को अकेला देख कर धमकी देते हुए उसके हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में ले गया। जान से मारने की धमकी देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर भाग गया। किशोरी ने घर पहुंचकर फोन से अपनी मां को जानकारी दी। गुरुवार को महिला अपने घर पहुंची तो किशोरी ने युवक का नाम बताते हुए घटना की जानकारी दी। महिला अपनी पुत्री को लेकर थाने पहुंची और घटना की पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने देर शाम घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस ने घर पर छापा मारा लेकिन आरोपी युवक पुलिस के हाथ नहीं लगा।

अयोध्या में बोले संत- मस्जिद समर्थक अब छोड़ें जिद, राम मंदिर निर्माण में करें सहयोग

अयोध्या। दि एक्यूजिशन एक्ट आफ सरटेन एरिया आफ अयोध्या को चुनौती देने वाली इस्माईल फारुखी बनाम यूनियन आफ इंडिया से सम्बन्धित याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्ष 1994 में दिए गए फैसले को सात जजों की बेंच को भेजने की मुस्लिम पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुरुवार को खारिज करने के फैसले पर संतों के साथ विहिप ने भी प्रतिक्रिया दी है। विहिप ने कहा कि इस फैसले से मंदिर निर्माण को बल मिलेगा। अब मस्जिद समर्थकों को बेवजह की जिद छोड़ देनी चाहिए। मंदिर निर्माण और न्यायालय से आये फैसले के प्रत्येक पहलुओं पर अब पांच अक्टूबर को दिल्ली में संत उच्चाधिकार समिति की बैठक में चर्चा होगी।

गुरुवार के सुप्रीम फैसले के बाद श्रीराम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने कहा कि मंदिर निर्माण होकर रहेगा, यह उम्मीद धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय मंदिर निर्माण में बाधक बने लोगों को अक्श दिखाने वाला है। ऐसे लोगों को अब स्वत- इस विवाद से हटकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन जाना चाहिए। श्रीराम जन्मभूमि न्यास के सदस्य महंत सुरेश दास ने कहा कि नमाज इस्लाम का हिस्सा है पर मस्जिद का नहीं परन्तु देवी-देवताओं की मूर्ति मंदिर का अटूट हिस्सा है जिसे अब मुस्लिमों को स्वीकार कर लेना चाहिए। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय मंदिर निर्माण के मार्ग को बल प्रदान करेगा।

हिन्दुओं की आस्था को खंडित करने का प्रयास जो लगातार चलता आ रहा उस पर कहीं न कहीं यह निर्णय प्रभाव डाल कर उसे कुंद करेगा। विहिप के केन्द्रीय सलाहकार पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने कहा कि मस्जिद में नमाज कोई आवश्यक नहीं है। नमाज जब कहीं भी जब पड़ी जा सकती है तो श्रीराम जन्मभूमि को विवादास्पद बनाना मुस्लिमों के हित में उचित नहीं है। यह निर्णय भविष्य को बल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा।

सनकादिक आश्रम पीठाधीश्वर व संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा कि यह फैसला लकीर पीटने वालों के लिए विचारणीय है। हिन्दुओं को मंदिर निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान श्रीराम भी चाहते हैं इसीलिये उनके सेवक बाधाओं को धीर-धीरे दूर कर रहे हैं।

68500 शिक्षक भर्ती- कॉपियां बदले जाने के मामले में हो रही धीमी जांच, सरकार को पड़ी फटकार

लखनऊ । 68 हजार 500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के खुलासे के बाद हो रही जांच से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने घोर असंतुष्टि जाहिर की है। न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अब तक की जांच रिपोर्ट को देखने से लगता है कि जैसे कोई विभागीय जांच हो रही हो जबकि जांच कमेटी को वास्तव में इस परीक्षा में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच करनी थी। न्यायालय ने मामले पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष सोनिका देवी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुईं लेकिन उन्होंने दलील दी कि उक्त गड़बड़ियां जानबूझकर नहीं हुईं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई। इससे असंतुष्ट न्यायालय ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार ठीक से जांच नहीं कर सकती तो कोर्ट उसे बताएगा कि जांच किस प्रकार की जाए। न्यायालय ने कहा कि वह इस प्रकरण में आदेश सुरक्षित कर रहा है जिसे बाद में लिखाया जाएगा। हालांकि न्यायालय ने आदेश सुरक्षित करने की बात कहने के बाद काफी देर तक महाधिवक्ता व याचीपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना।उल्लेखनीय है कि उक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया था कि याची की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गई है। उत्तर पुस्तिका बदलने की बात सामने आने पर महाधिवक्ता ने कई और अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने की बात स्वीकारते हुए, न्यायालय को आश्वासन दिया था कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

न्यायालय के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने 8 सितम्बर को प्रमुख सचिव, गन्ना उद्योग संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कमेटी के सुपुर्द कर दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान भी न्यायालय ने जांच के सम्बंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अगली सुनवाई पर यदि जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं होती तो जांच कमेटी के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से मय रिकॉर्ड हाजिर होना होगा।

बरेली- तीन तलाक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उलेमा

बरेली। तीन तलाक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में उलेमा चुनौती देंगे। मुंबई और बरेली से उलेमा का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर मामले में कानूनी पैरवी की शुरुआत कर दी है। उलेमा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताते हुए इसको शरीयत के खिलाफ बताया है। उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से मशवरा लेकर फाइल तैयार कराई है।

तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि तीन तलाक अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इसके लिए दिल्ली जाकर प्रतिनिधि मंडल ने अधिवक्ताओं से जानकारी ली है। याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से मशवरा किया गया है। मौलाना ने कहा कि अध्यादेश के लिए विरोध नहीं है, लेकिन जो शरीयत की मुखालफत में हो, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। मुंबई रजा एकडेमी के महासचिव मौलाना सईद नूरी ने कहा कि शरीयत में दखलअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की जा रही है। केंद्र सरकार जानबूझकर मुसलमानों के मसाईल पर चोट कर उन्हें परेशान कर रही है। तीन तलाक के अलावा देश भर में दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। सुन्नी बरेलवी मसलक के उलेमा ने तीन तलाक अध्यादेश का विरोध शुरू कर दिया है।

ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ दवा की दुकाने बंद, मरीजों को हो रही परेशानी

दवा व्यापार में ई-फॉर्मेसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त को जारी ड्रॉफ्ट के विरोध समेत अन्य मांगों के समर्थन में दवा व्यापारियों ने पूरे प्रदेश में शुक्रवार को दुकानें बंद रखीं। दवा व्यापारियों का कहना है कि ई-फॉर्मेसी को बढ़ावा देने से इसका असर सीधे मरीजों पर पड़ेगा। लोग गलत दवाएं मंगा लेंगे। उनकी जांच के लिए सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दवा दुकानें ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बैनर तले पूरे भारत में बंद का असर देखने को मिला। मरीज और तीमारदार दवा लेने के लिए बाजारों में भटकते रहे। वहीं, सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा लेने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। अधिक भीड़ और अव्यवस्था के चलते सरकारी अस्पताल में तो कई जगह मरीज बिना दवा लिए लौट गए।

हालांकि आपात स्थिति में अस्पतालों और नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर को इससे छूट दी गई है। दवा विक्रेता संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी से दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यही नहीं इसका असर दुकानदारों और उससे जुड़े कर्मचारियों के रोजगार पर भी पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर में मेडिकल स्टोर के अलावा संयुक्त व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद की। गाजियाबाद के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह व्यापारियों ने जाम लगाया और मेडिकल स्टोर समेत कई दुकाने बंद की। दवा की दुकानें बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।झारखंड के कोल्हान में व्यापारियों के भारत बंद का मिलाजुला असर है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में कहीं दुकानें बंद हैं तो कहीं खुली हैं। हालांकि दवा की दुकानें बंद हैं। कदमा में सभी दुकानें खुलीं हैं,जबकि बिष्टूपुर में दुकानें बंद हैं। साकची की सभी दवा दुकानें बंद है जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन ने साकची चौधरी बिल्डिंग के निकट धरना दिया। जुगसलाई बागबेड़ा रोड में बंद दुकाने हैं। पेट्रोल पंप भी बंद है। घाटशिला समेत अन्य शहरों में दवा की दुकानें बंद हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा,चक्रधरपुर समेत अन्य शहरों में दवा की दुकानें बंद हैं। सरायकेल-खरसावां में ऐसी ही स्थिति है।ई-फार्मेसी एक्ट के विरोध में राजधानी देहरादून में आज दवा कारोबारी हड़ताल पर हैं। दवा की दुकानें बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के सभी केमिस्ट दून अस्पताल के पास जैन मेडिकल हाल पर एकत्र हुए हैं। यहां से डीएम कार्यालय कूच कर पीएम के नाम एक ज्ञापन देंगे।

पढ़ने का रिकॉर्ड बनाने में यतीश ने पूरा किया 72 घण्टे का सफर

लखीमपुर-खीरी। लगातार पढ़ने का रिकॉर्ड बनाने में लगे यतीश शुक्ला ने शुक्रवार की सुबह 72 घंटे का सफर पूरा कर लिया है। गोला में हो रहे इस ग्लोबल इवेंट को देखने के लिए जिलेभर से छात्र टीचर और अधिकारी पहुंच रहे हैं।गोला कस्बे के यतीश चंद्र शुक्ला ने ठाना है कि नाइजीरिया के नाम दर्ज 122 घंटे लगातार पढ़ने के रिकॉर्ड को अब वह भारत के नाम कर के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मंगलवार की सुबह 8-09 पर यतीश शुक्ला ने पढ़ना शुरू किया था। 80 घंटे तक लगातार श्रीमद्भागवत गीता का हिंदी अनुवाद वाचन करने के बाद अब यतीश शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। इस दौरान यतीश पढ़ते-पढ़ते ही जूस पी रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते ही डॉक्टर उनका चेकअप भी कर जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह 8-30 पर यतीश ने 72 घंटे का रिकॉर्ड पूरा कर लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद रवि प्रकाश वर्मा का कहना है यतीश विश्व रिकार्ड से ज्यादा दूर नहीं है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत के नाम सबसे ज्यादा पढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। गुरुवार की रात यतीश का हौसला बढ़ाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ आरके जायसवाल भी पहुंचे। इसके अलावा एसडीएम अखिलेश यादव रात को यतीश को सुनने के लिए पहुंचे।

क्रांति समय

अहमदाबाद-दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस बुरहानपुर स्टेशन पर ठहरेगी

सूरत। रेल मंत्री पियूष गोयल की पहल पर रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन सं या 15559/15560 अहमदाबाद-दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस को 29 सितंबर से मध्य रेल भुसावल मंडल के भुसावल खंडवा के बीच स्थित बुरहानपुर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त ठहराव आगामी छह माह के लिए प्रायोगिक तौर पर प्रदान किया जा रहा है।

सूरत। सर्जिकल स्ट्राईक के 2 साल पुरे होने पर 28 व 29 सितम्बर को शहर भर में जश्न मनाया जा रहा है। आज एडिटोरियल हाल बी.सी.ए बिल्डींग 1 फ्लोर, अमरोली कोलेज सूरत किया गया।

वराछा पुलिस ने 11 लाख की डुप्लीकेट घड़ीयों के साथ एक को पकड़ा

सूरत। वराछा विस्तार में 11 लाख की डुप्लीकेट घडीयों के साथ एक व्यक्ति को पकड़ है। इन घड़ीयों में अलग-अलग ब्रांड की इंपोर्टेट घड़ीया है जिसकी मार्केट के हिसाब से कुल 11 लाख 25 हजार किमत बताई जा रही है। वराछा पर हंस सोसायटी के पास जय अंबे वोय नामकी दुकान में से इस माल को पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

बेंगालुरू में उपचार करा अहमदाबाद लौटे हार्दिक पटेल

अहमदाबाद। बेंगालुरू स्थित जिंदल नेचरक्योर में उपचार करवाने के बाद पास नेता हार्दिक पटेल आज अहमदाबाद लौट आए और फिर एक बार आंदोलन शुरू करने के संकेत दिए।

गुजरात में किसानों की कर्ज माफी, पाटीदारों को आरक्षण और अल्पेश कथीरिया की रिहाई की मांग को लेकर 25 अगस्त से आमरण अनशन शुरू किया था। पाटीदार समाज की छह धार्मिक संस्थाओं की मध्यस्थता के बाद हार्दिक पटेल ने 19वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। इस दौरान हार्दिक पटेल की तबियत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनशन खत्म होने के बाद हार्दिक पटेल उपचार के लिए बेंगालुरू स्थित जिंदल नेचरक्योर गए थे। जहां से उपचार करवाने के बाद आज सुबह की 10 बजे के लाइट से हार्दिक पटेल अहमदाबाद लौट आए। अहमदाबाद लौटे हार्दिक पटेल ने फिर एक बार आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आगामी 2 अक्टूबर को मोरबी से हार्दिक पटेल फिर एक बार आंदोलन का श्रीगणेश करेंगे। हांलाकि अबकि बार भूख हड़ताल नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में प्रतीक उपवास करने की योजना है।

स्वाइन फ्लू से वृद्ध की मौत, परिवार का उपचार में लापरवाही का आरोप

सूरत। शहर के सगरामपुरा स्थित निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से एक वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध की मौत से गुस्साए परिवार ने इलाज में आरोप लगाते हुए अस्पताल में भारी हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की है।

जानकारी के अनुसार सूरत डभोली में रहनेवाली उत्तर प्रदेश के मूल निवासी स्वामीनाथ मिश्रा को तबियत बिगड़ने के बाद गत 18 सितंबर को सगरामपुरा स्थित व्हाइट हाउस के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां तबियत बिगड़ने के बाद स्वामीनाथ मिश्रा को वेन्टीलेटर पर रखा गया। लगातार 9 दिन के उपचार के बाद गुरुवार की रात स्वामीनाथ मिश्रा की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि उपचार के दौरान वेन्टीलेटर बंद हो गया था, जिसकी वजह स्वामीनाथ मिश्रा की मौत हो गई। अस्पताल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने स्वामीनाथ मिश्रा का शव लेने से इंकार कर दिया। घटना से गुस्साए परिवार के हंगामा करने पर पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के सिविल अस्पताल भेज दिया। मृतक के पुत्र ने कहा कि 2 लाख से भी अधिक खर्च किए जाने के बावजूद उपचार में यदि ऐसी लापरवाही की जाती है तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री का नगरों के बीच स्वच्छ-सुविधापूर्ण नगरों की आंतरिक स्पर्धा का आह्वान

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के नगरों के बीच स्वच्छ नगर- सुविधापूर्ण नगरों के लिए आंतरिक स्पर्धा आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नगरों में सड़क, गटर, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के कार्यों में गति, तेजी और पारदर्शी प्रशासन के लिए प्रादेशिक युनिसिपल कमिश्नर्स के जो विभाग बनाए गए हैं उनके साथ जिला कलक्टर्स- राज्य सरकार, स बन्धित नगरपालिका के प्रमुखों- चीफ ऑफिसर्स के बीच सुदृढ़ संकलन हो, यह हमारा संकल्प है। इस उद्देश्य को लेकर चारों रीज़न के मनपा कमिश्नर्स, युनिसिपल प्रमुख और चीफ ऑफिसर्स को समय समय पर कामकाज की समीक्षा और रिव्यु करना चाहिए।

विजय रूपाणी ने सीएम डेशबोर्ड के मार्फत गांधीनगर के मुख्यमंत्री आवास से राज्य की नगरपालिकाओं के विकास कार्यों और जनहितकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मण्डल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक स पन्न

अहमदाबाद। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर 01 अक्टूबर 2017 से 30 सित बर 2019 के लिए गठित मण्डल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक मण्डल कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें समिति के अध्यक्ष व मण्डल रेल प्रबंधक दिनेशकुमार एवं समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक अजय प्रकाश सदस्यगण मौजूद रहे।

बैठक में दिनेशकुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 200 अतिरिक्त कोच लगायेहै, जिससे 16 करोड रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है तथा 86 स्पेशल ट्रेनो का संचालन किया गया है। माललदान आय में इस वार 8 प्रतिशत की वृध्धि दर्ज की गई है। स्वच्छता ईश्वरीय स्वरुप है की अवधारणा पर स्टेशनों व ट्रेनों की साफ सफाई को और बेहतर बनाया जा रहा है। सभी स्टेशनों पर सफाई के लिए ठेके आवंटित कर दिये गये है। गंदगी फैलाने वालों के विरुध्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अभी 1275 व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है। उन्होने बताया कि हमारा प्रयास है कि सित बर 2019 तक मण्डल के प्रत्येक स्टेशन पर दिव्यांगो के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी जायेगी। सभी बडे स्टेशनों पर नये बेहतर कोच गाईडेंस सिस्टम लगाये जा रहे है। गांधीधाम सहित अन्य स्टेशनों पर कवर शेड बढाने का फेंसला लिया है। भुज स्टेशन पर हाल ही में स्थानीय संस्कृति के अनुरुप आकर्षक मड पेंटिंग लगाई गई है। उन्होने बताया कि मण्डल के उन स्टेशनों पर जहां प्लेटफार्म छोटे है, उन सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म विस्तार का कार्य हाथ में लिया गया है, अहमदाबाद स्टेशन पर सफाई के प्रति अपने विचार/सुझाव मशीने के लिये मशीने लगाई गई है, तथा गंदगी के लिए व्हाट्सअप न बर भी जारी किया गया है। सभी प्लेटफार्म पर लि ट का प्रावधान किया गया है एवं नया एस्केलेटर लगाया जा रहा है। अहमदाबाद स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। अंजार स्टेशन पर एक नये फुटओवर ब्रिज एवं प्लेटफार्म का काम स्वीकृत किया गया है।

सरकार को किसानों की गुजरात की ज नता की कोई चिंता नहीं है

अहमदाबाद । बेंगलुरु के जिंदाल नेचरक्योर में उपचार कराकर अहमदाबाद वापस आये पास कन्वीनर हार्दिक पटेल ने शुक्रवार आने के साथ ही फिर एकबार गुजरात सरकार पर कड़े प्रहार किए। भाजपा सरकार और विधायकों को किसानों या गुज रात की जनता की कोई चिंता नहीं है । लहसुन -प्याज सहित की सब्जी की कीमत कम हो गई फिर भी किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है यह संवेदनहीन सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। विधायक आत्महत्या कर लेते यह कहकर हार्दिक ने विधायकों पर निशाना साधा।

स्वाइन फ्लू के १९० मरीज अभी उपचार के तहत

स्वाइन फ्लू से गुजरात में भारी दहशत : और तीन की मौत हुई

अहमदाबाद। स्वाइन फ्लू की वजह से राज्य में फिर से एकबार आतंक मचाया हुआ है । स्वाइन फ्लू के केस में चिंताजनक तरीके से वृद्धि हो रही है । शुक्रवार को और लोगों की मौत होने पर प्रशासन में खलबली मच गई । इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़कर १७ पर पहुंच गया। स्वाइन फ्लू के कारण शुक्रवार को राज कोट, अरवल्ली और खेडा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। सितम्बर महीने में स्वाइन फ्लू के ५४९ केस सामने आ चुके हैं जिसमें से अभी भी १९० मरीज अभी उपचार के तहत होने की जानकारी मिली है जबकि ३४२ मरीजों को उपचार देने के बाद उनको अस्पताल में से छुट्टी दे दी गई है। राज्यभर में अब स्वाइन फ्लू के मरीज सीजनल फ्लू के मरीज के तौर पर केस पेपर में दर्ज होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अब स्वाइन फ्लू को सीजनल फ्लू की आधिकारिक नाम दिया है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर लोगों में नाराजगी फैल चुकी है क्योंकि स्वाइन फ्लू के मरीजों का सही आंकड़े को छिपाये जाने का प्रयास होगा और सही मौत के आंकड़े और मरीजों का आंकड़ा सामने नहीं आ सके ऐसी दहशत भी जागरूक नागरिकों ने व्यक्त की है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ नियामक परेश दवे ने बताया है कि, राज्यभर में अब स्वाइन फ्लू सीजनल फ्लू नाम से जाना जाएगा । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सूचना बाद भारत सरकार ने राज्य को की गई सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है । दूसरी तरफ निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को स्वाइन फ्लू पोजीटिव आने के बाद इसे कम उपचार में अन्य अस्पताल में रिफर नहीं किया जा सकेगा।

ऐसा होगा तो एपिडेमिक एक्ट-१८९७ के अनुसार इसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी नोडल ऑफिसर के साथ सीजनल फ्लू के मुद्दे तथा शहर और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें उनको स्वाइन फ्लू के बदले में सीजनल फ्लू केस पेपर में लिखने के लिए बताया जाएगा । वर्ष २००९ में एच-१ एन-१ के घातक वाइरस को स्वाइन फ्लू के तौर पर घोषित किया गया था।

खानपुर भाजपा ऑफिस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

ऑनलाइन दवा की बिक्री के विरोध में दवा की दुकाने बंद

अहमदाबाद । ऑनलाइन दवाईयों की बिक्री ई-फार्मसी के विरोध में शुक्रवार को अहमदाबाद शहर की ५००० से ज्यादा और राज्य की ३५ हजार से ज्यादा दवा की दुकानों ने शुक्रवार को बंद रखने पर मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा, सामान्य लोगों को भी रूटीन दवाई लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। दवाओ की ऑनलाइन बिक्री और इसे प्रोत्साहन देने पर केन्द्र के अध्यादेश का दवा की दुकानवाले फार्मासीस्टों ने बंद रखकर विरोध प्रदर्शित किया है। हालांकि बंद के ऐलान के दौरान लोगों को कोई समस्या नहीं हो इसके लिए स्टेट कैमीस्ट एंड ड्रगीस्ट एसोसिएशन ने अहमदाबाद में १२ क्षेत्रों में दुकान खुला रखने का निर्णय लिया और हरएक जिले में भी कई दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया गया था लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

केन्द्र सरकार ने दवाई की ऑनलाइन बिक्री-फार्मसी की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए गत महीने में नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट एंड ड्रगीस्ट एसोसिएशन ने विरोध किया है । इसके साथ-साथ वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट के कनेक्शन के विरोध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दिए गए बंद का ऐलान विफल रहा। एसोसिएशन की गुजरात ब्रांच के प्रेसिडेन्ट अल्पेश पटेल ने बताया है कि, सरकार ने जारी किए नोटिफिकेशन में कई विसंगतता है । ऑनलाइन दवाई की बिक्री करती कंपनी की कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई है । ई-फार्मसी बंद होनी चाहिए । जैसे नियम के अनुसार ग्राहक को कैमिस्ट द्वारा ही दवाई दिया जा सकता है यह नियम का भंग होगा । अब भारत सरकार-ई-फार्मसी को वैध करने जा रही है तब इसके विरोध में शुक्रवार को राज्यभर के मेडिकल स्टोर बंद रखकर इसका विरोध व्यक्त किया है । शुक्रवार को सरकार के विरोध में काली पट्टी धारण करके मार्गों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com